कोटपूतली में प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 68 दुकानें व कई इमारतों को ध्वस्त किया।

कोटपूतली में प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़े

मास्टर प्लान के तहत हुई इस कार्यवाही के पहले चरण में 68 दुकानें व अन्य इमारतें तोड़ी गईं

- नगर परिषद प्रशासन ने भारी पुलिस जाप्ते के साथ सुबह 5 बजे से संरचनाएं तोड़ने की कार्यवाही की शुरू।
- कार्यवाही का विरोध करने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल सहित आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया।
- आधे शहर में बिजली पानी व इंटरनैट सेवायें ठप्प हुईं।

कोटपूतली, 6 अगस्त (निसं)। नगर परिषद प्रशासन ने कोटपूतली में मास्टर प्लान 2011 के अनुरूप कस्बे के मुख्य चौराहे से लेकर नगरपालिका तिराहा तक 80 फीट व पूर्व सिनेमा से लेकर पूतली कट तक 60 फीट सड़कों को चौड़ा करने की कार्रवाई की। इसके लिए प्रशासन सुबह करीब 5 बजे एलएनटी, जेसीबी व पोपलैण्ड मशीनों व भारी मात्रा में स्टाफ कर्मियों सहित पुलिस का अमला निर्माण हटाने के लिए पहुंचा।

शनिवार को एलबीएस कॉलेज के छात्रावास की ओर 22 दुकानों समेत पुरानी नगर पालिका तिराहे पर अग्रसेन सर्किल के पास शेखावत भवन, भरगड़ प्लाजा, कौशिक मार्केट, पुस्तक मार्केट में करीब 68 दुकानें हटाई गई। प्रशासन द्वारा गठित चारों टीमों ने एक साथ कार्यवाही कर सुबह करीब 10 बजे तक अधिकांश संरचनाओं को ध्वस्थ कर दिया था। इस दौरान कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों के व्यापारी सामान तक नहीं उठा पाये थे कि प्रशासन की अतिक्रमण ध्वस्त मशीनें इमारतों को जमीरोंध करती नज़र आईं। कार्यवाही के दौरान पहले फेज में कुल 68 इमारतों को ध्वस्थ किया गया।

इसी बीच महालक्ष्मी मिष्ठान भण्डार के पास अमृत कैलेक्शन शोरूम पर कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान परिषद का एक कर्मचारी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही कर्मचारी के बेहोश होने की भनक प्रशासन को लगी तो अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई और आनन-फानन में उक्त कर्मचारी को एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान कार्यवाही यथावत जारी रही। देर रात तक प्रशासन की जेसीबी, हाईवा व ड्रिल मशीनें चलती रही। आनन-फानन में की गई कार्यवाही से जहां बिजली विभाग को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, वहीं दिनभर लोग बिजली, पानी व इन्टरनेट सेवाओं को तरसते रहे। इधर प्रशासन की कथित दमनात्मक कार्यवाही का विरोध करने पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश गोयल, एडवोकेट बजरंग लाल शर्मा, एडवोकेट मनोज नारायण शर्मा, भाजपा नेता सुभाष घोघड़, भाजपा नेता प्रवीण बंसल व संघर्ष समिति के पंडित किशोरलाल नेताजी को हिरास्त में ले लिया गया। इस दौरान विरोध करने आये लोगों से प्रशासनिक अधिकारियों की तीखी नोंक-झोंख भी हुई।

लोगों का आरोप था कि प्रशासन राजनैतिक दबाव में आकर व्यापारियों के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही कर रहा है, जो कोटपूतली की जनता की भावनाओं पर कुठाराघात है। प्रशासनिक कार्यवाही को आमजन दो नजरिए से देख रहा है। एक तो विकास के आईने से और दूसरा विकास की जगह विनाश के आईने से। कार्यवाही के दौरान एडीएम जगदीश आर्य, एसडीएम ऋषभ मण्डल, मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार सूर्यकान्त शर्मा, एएसपी विद्या प्रकाश, यातायात एएसपी सुमित गुप्ता, डीएसपी डॉ. संध्या यादव, शाहपुरा डीएसपी सुरेन्द्र कृष्णियां, एसएचओ सवाई सिंह सहित पनियाला, सरूण्ड, प्रागपुरा, चंदवाजी, शाहपुरा, भाबरू समेत 8 थानों का पुलिस जाप्ता एवं एसटीएफ जवानों की पूरी कम्पनी को मिलाकर करीब 500 जवान सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहे। नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा के नेतृत्व में निर्माण हटाने की समस्त कार्यवाही की गई।

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में शनिवार को करीब 68 निर्माण हटाये गये है। साथ ही स्टे वाले निर्माणों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। अगली कार्यवाही द्वितीय चरण में स्वतंत्रता दिवस के बाद की जायेगी, जिसके लिए अलग से नोटिस भी जारी किये जायेगें। जबकि तृतीय चरण में नीलाम की गई सम्पत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। एडीएम जगदीश आर्य ने आमजन व व्यापारियों को प्रशासन का सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया है।

गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा मुख्य चौराहे से अग्रसेन सर्किल व आसपास के सम्पत्ति मालिकों को शुक्रवार को ही 24 घण्टों में निर्माण हटाने के निर्देश दिये गये थे। आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने यह भी बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही समस्त कार्यवाही पूर्णतया: शांतिपूर्ण तरीके से की गई है, जिसमें स्थानीय व्यापारियों का भी प्रशासन को भरपूर सहयोग मिला है। व्यापारियों ने स्वयं ही अपनी दुकानों को पहले ही खाली कर लिया था। परिषद द्वारा दोनों मुख्य मार्गो को मास्टर प्लान के तहत क्रमश: 80 व 60 फिट चौड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि विगत दिसम्बर 2021 में भी उक्त कवायद के चलते आम नोटिस व व्यक्तिगत नोटिस के माध्यम से दोनों मार्गो को चौड़ा करने की कार्यवाही शुरू की गई थी। इसके विरोध में एक ओर जहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। वहीं सम्पत्ति मालिकों ने उक्त कार्यवाही को विधि विरूद्ध बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकायें दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने नगर परिषद को व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए 30 दिवस में विस्तृत एवं सकारण आदेश पारित करने व तब तक याचीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही ना करने के निर्देश दिये गये थे। साथ ही नगर परिषद को मौका एवं दस्तावेजों की जाँच कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करते हुए प्रभावितों की मुआवजा राशि तय करने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

बीठनोक में 250 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट लगाने पर केन्द्र व राज्य सहमत

राज्य की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा और केन्द्र के कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एम. नागाराजू के बीच जयपुर में इन परियोजनाओं पर चर्चा हुई

- इसके अतिरिक्त बीठनोक में ही 300 मेगावाट का एक और प्लांट व बरसिंगसर में 250 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

बीकानेर, 6 अगस्त (कासं)। बीकानेर जिले के बीठनोक गांव में 250 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट लगाने पर केन्द्र और राज्य सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं।एनएलसी इंडिया लिमिटेड इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर बनाने में जुट गया है। जल्द एमओयू और इंस्टालेशन की प्रक्रिया शुरू होने का अनुमान है।

राज्य और केन्द्र के उच्चाधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में इस प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक सहमति के साथ ही बीठनोक में ही 300 मेगावाट के सोलर प्लांट और बीकानेर के बरसिंगसर में 250 मेगावाट के लिग्नाइट पावर प्लांट के एक्सटेंशन पर भी बातचीत हुई है। ऐसे में ये दोनों प्लांट भी मंजूर हो जाते हैं तो जिले में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन का रास्ता खुलेगा।

राज्य की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा और केन्द्र के कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एम. नागाराजू के बीच जयपुर में इन परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई यह प्रक्रिया कई कारणों से आगे नहीं बढ़ पाई। मीटिंग के बाद चीफ सैक्रेट्री ने बीठनोक में 250 मेगावाट प्लांट के लिए नए सिरे से डीपीआर बनाने का निर्देश दिया है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट हैड जगदीश मजूमदार ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हम नए सिरे से पूरी योजना बनाकर सरकार को दे रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि बीठनोक में लिग्नाइट पावर प्लांट का एमओयू हो चुका था। बिजली की लागत लगभग पांच रुपए यूनिट आ रही थी।

पूर्ववर्ती सरकार ने रेट ज्यादा बताकर एमओयू तोड़ दिया। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह प्लांट शुरू करवाने का आग्रह किया था। इस पर अब केन्द्र-राज्य दोनों मिलकर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े हैं। उम्मीद है जल्द उत्पादन शुरू होगा।

जगदीप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्रमश: ओम बिड़ला और जगदीप धनखड़। दिलचस्प बात ये है कि धनखड़ को कृष्णकांत, भैंरोसिंह शेखावत, हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू से भी अधिक वोट मिले, जो भी एक रिकॉर्ड है। ऐसा लोकसभा में भाजपा के भारी बहुमत के कारण हुआ।

आर.सी.पी. सिंह का नीतीश की पार्टी से इस्तीफा

नई दिल्ली, 6 अगस्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइड हैंड माने जाने वाले जे.डी.यू. के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.सी.पी. सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जे.डी.यू. ने आर.सी.पी. सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आर.सी.पी. सिंह पर साल 2013 से 2022 के बीच अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है। जे.डी.यू. ने आर.सी.पी. सिंह को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि 9 सालों में आपको परिवार के नाम पर 58 प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है। इस तरह कुल 800 कट्ठा जमीन की खरीद हुई है।

भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बर्मिंघम कॉमनवैल्थ गेम्स में महिला 53 कि. ग्रा. वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कॉमनवैल्थ गेम्स में यह भारत का ग्यारहवां गोल्ड है।

नीतीश कुमार व के.सी.आर. ने प्र.मंत्री मोदी की बैठक में शामिल होने से इन्कार किया

- प्र.मंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के संबंध में मु.मंत्री के.सी.आर ने कहा, भेदभाव के कारण बैठक से हमारे राज्य को कोई फायदा होने वाला नहीं है।
- नीति आयोग की 7 अगस्त को होने वाली बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।

नई दिल्ली, 6 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की बैठक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब तेलंगाना के सी.एम. के चंद्रशेखर राव ने भी किनारा कर लिया है। बैठक में हिस्सा नहीं लेने के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री राव ने कहा कि उन्हें नीति आयोग की बैठक से कोई फायदा नहीं दिख रहा है। रविवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने वाली है।

के.चंद्रशेखर राव ने कहा, मैं विरोध के रूप में कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 70वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसके साथ-साथ राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्यों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनकी जरूरतों और शर्तों के आधार पर योजनाओं को डिजाइन और उसमें बदलाव किए जाने की व्यवस्था नहीं दिए जाने को लेकर केंद्र के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है।

के.सी.आर. ने पी.एम. मोदी के लिखे पत्र में कहा है, भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है, जब राज्यें विकसित हों। उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से जीवंत राज्य ही भारत को एक मजबूत देश बना सकते हैं।

मैं भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के हमारे सामूहिक प्रयास में राज्यों के साथ भेदभाव करने और उन्हें समान भागीदार के रूप में नहीं मानने के केंद्र सरकार के वर्तमान रुख के खिलाफ इस बैठक से दूर रहूंगा।

धमोरा गांव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वॉलीबाल से जुड़ा हुआ है। कप्तान दुष्यंत के अलावा टीम में अमन कुमार, जोशनुर ढींडसा, संदीप, अजय कुमार, समीर चौधरी, तनिश चौधरी, हर्षित गिरी, जिबिन जॉश, सचिन डागरी, मन्नत चौधरी, कार्तिकेयन के (लिब्रो), अजीत शेखों, सूर्यप्रकाश बंजारा (लिब्रो) को जगह दी गई है।

टीम मैनेजर कुलदीप राज मगोत्रा, चीफ कोच जेई श्रीधरन, असिस्टेंट कोच राजेश कुमार, प्रवीन शर्मा, अंतराष्ट्रीय निर्णायक शेख एजाज सिकंदर होंगे।

झुंझुनूं जिले में जाखड़ों की ढाणी को वॉलीबाल खिलाड़ियों की खान कहा जाता है। जहाँ से कई अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं और 20 से 25 राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं।

शुरू से लेकर वर्तमान तक 50 के लगभग राज्य स्तर के खिलाड़ी भी इसी ढाणी के हैं। इनमें से अधिकांश तो सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं।

प्र.मंत्री व गृह मंत्री के स्पष्ट निर्देश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा फिलहाल वरूण गांधी की उग्र आलोचनाओं को मित्रवत लेने का भाव प्रकट कर रही है। अभी हाल ही में, उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाये जा रहे उन आरोपों को लेकर निशाना साधा था, जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के अभियान के दौरान, प्रश्न पत्र लीक होने के बारे में लगाये जा रहे हैं।

सरकार द्वारा उम्रदराज लोगों को रेल किराये में दी जा रही छूट को समाप्त कर देने, पैकेज्ड खाद्य पदार्थो पर जी.एस.टी. लगाये जाने तथा सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की नई स्कीम "अग्निपथ" शुरू करने के लिये भी वरूण गांधी ने केन्द्र सरकार की कड़ी आलोचना की थी।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पार्टी को विशेष निर्देश दिये गये हैं कि वरूण गांधी की अठखेलियों अनदेखी की जानी चाहिए तथा तब तक पार्टी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए जब तक कि वे सीमा पार न कर जाएं।

लेकिन अगर वरूण गांधी को पार्टी की कीमत पर मीडिया में जगह मिलने दी जाती है तो यह पार्टी और सरकार दोनों में से किसी के हित में नहीं होगा।

जहाँ वरूण गांधी यह चाहते हैं कि पार्टी उन्हें निष्कासित करे तथा उसके बाद वे अपनी सीट को बरकरार रखें, वहीं भाजपा यह सोचकर सुरक्षित खेल खेल रही है क्योंकि वरूण के खिलाफ कोई कदम उठाये जाने से बहुत बड़ी बहस छिड़ जायेगी, क्योंकि वरूण गांधी की माँ मेनका गांधी 1990 के दशक में उस समय भाजपा में आई थीं, जब भगवा दल एल.के.अडवाणी तथा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गैर-आर.एस.एस. नेताओं को आमन्त्रित कर रहा था ताकि जनता में इसका प्रसार अपेक्षाकृत अधिक व्यापक स्तर पर हो सके। 65 वर्षीय मेनका गांधी जनता दल टिकट पर पीलीभीत से जीतकर विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में राज्य मंत्री बन गई थीं। वे वाजपेयी सरकार तथा मोदी सरकार में भी 2014 से 2019 तक मन्त्री रही, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में मिली जीत के बाद, वे उपेक्षित कर गईं। वे 2019 लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर से जीती थीं।

जहाँ मेनका गांधी ने लोकसभा में अपेक्षाकृत कम मुखर रहना उचित समझा तथा वे चर्चा में यदाकदा ही भाग लेती थीं, वहीं वरूण गांधी लोकसभा में भाजपा तथा नेतृत्व पर तंज करने वाले तथा उन्हें असुविधाजनक लगने वाले प्रश्न पूछना पंसद करते हैं।

केन्द्रीय सरकार व तमिलनाडू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे भयभीत हुए बिना, तमिलनाडु के तेज तर्रार वित्त मंत्री पी. त्यागराजन ने पलटवार करते हुये कहा कि राज्य के प्रतिनिधि ने बहुत सी वस्तुओं पर जी.एस.टी. लगाने का मौखिक एवं लिखित विरोध किया था तथा उन्होंने स्वयं ने राज्य की आपत्तियों को भी लिख कर दिया था। पी.टी.आर., जिस नाम से वे जाने जाते हैं, के पास उसी समय से जी.एस.टी. का पूरा ब्यौरा है, जब पिछले वर्ष डी.एम.के. जोर-शोर से सत्ता में आई थी। उनका कहना है कि जी.एस.टी. काउंसिल की रूपरेखा में ही खामियाँ हैं तथा इसकी निर्णय प्रक्रिया में राज्यों को अपने अलग मत व्यक्त करने की कोई गुजांइश ही नहीं बची है।

जी.एस.टी. काउंसिल की वर्तमान मतदान पद्धति, जिसमें केन्द्र के 33 प्रतिशत वोट हैं, केवल केन्द्र का ही पक्ष लेती है। उन्होंने कहा कि अगर परिषद का कोई सदस्य कोई प्रस्ताव लाता है तथा केन्द्र सरकार उस पर नकारात्मक रुख अपना लेती है, तो वह प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। जब हम केन्द्र से अनुरोध करते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में जनता को राहत दो, तो जी.एस.टी.-व्यवस्था लागू होने के बाद, उस अनुरोध का यही हश्र होता है। राज्यों के पास टैक्स बढ़ाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ऐसा करने का अधिकार केवल केन्द्र के पास ही है। उन्होंने कहा कि आज केन्द्र जो एक्साइज वसूलता है, वह 2014 की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। त्यागराजन ने एक ट्वीट में पूछा, "इसके अलावा, पेट्रोल एवं डीज़ल पर टैक्स कम किसको करना चाहिए? क्या यह काम केन्द्र सरकार को नहीं करना चाहिये, जिसने पिछले 7 वर्षों में ईंधन पर अनेक बार टैक्स बढ़ाया है? या यह काम डी.एम.के. को करना चाहिये, जिसने अब तक के इतिहास में एक बार भी ईंधन पर टैक्स नहीं बढ़ाया?

उनके पास इस बात का युक्तियुक्त कारण है कि केन्द्र प्राय: तमिलनाडु पर हमले क्यों करता है। उनके अनुसार, इसका कारण यह है कि आर्थिक मोर्चे पर तमिलनाडु का प्रदर्शन केन्द्र सरकार की अपेक्षा बेहतर है।

पी.टी.आर. ने कहा, "इस साल केन्द्रीय बजट में राजकोषीय घाटा 7 प्रतिशत है, हमारा करीब 3.5 प्रतिशत था। आज देश में महँगाई 8 प्रतिशत के आसपास है, हमारी 5 प्रतिशत के आसपास ही है। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, हमारी सरकार करुणा तथा सामाजिक न्याय दर्शाती है, किन्तु उसकी बावजूद, बेहतर परिणाम देती है। और इससे दिल्ली में बैठी उपनिवेशवादी ताकतें चिढ़ती हैं। पी.टी.आर. ने अफसोस व्यक्त करते हुये कहा कि आज जब डी.एम.के. के उन्हीं सिद्धान्तों को अपना रही है, जो राज्यों के अधिकारों का समर्थन करने के लिये मोदी जी ने उस समय अपनाये थे, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हमारे इस काम को सीधे टकराव के रूप में देखा जा रहा है।

प्रियंका गोस्वामी ने कॉमनवैल्थ गेम्स में शनिवार को महिला 10 किमी. रेस वॉक (स्टीपलचेज़) में ऐतिहासिक सिल्वर मैंडल हासिल किया। प्रियंका रेसवॉकिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। वे इस खेल में कॉमनवैल्थ मैंडल जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी भी हैं। इससे पहले, हरमिंदर सिंह ने दिल्ली 2010 कॉमनवैल्थ गेम्स की 20 किमी. रेसवॉकिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। प्रियंका गोस्वामी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 10,000 मीटर की दूरी को 43:38 मिनटों में पूरा किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जेमीमा मॉनटाग ने 42:34.00 के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रियंका ने सीटी बजते ही ट्रैक पर बढ़त हासिल कर ली थी और 4,000 मीटर के बाद वो पहले स्थान पर थीं। इसके कुछ देर बाद ही वो जेमीमा और कीनिया की एमिली वामुस्यी एन्जी से पिछड़ गयीं। जब प्रतियोगिता में सिर्फ दो किमी की दूरी बची थी, तब प्रियंका ने शानदार वापसी करते हुए कीनिया की प्रतिद्वंदी को पछाड़ा और सिल्वर मैंडल हासिल किया।

रिलायंस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गुरूमूर्ति ने जनवरी 2002 में दायर की थी। याचिका में शिकायत की गई थी कि 1994 में 12 करोड़ इक्विटी शेयरों के आवंटन में चालबाजी हुई थी। ये शेयर कथित रूप से आर.आई.एल. के प्रमोटरों, आर.आई.एल. द्वारा वित्त पोषित ग्रुपों एवं कम्पनियों को आवंटित कर दिये गये थे। मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमना, न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी तथा हिमा कोहली की बैंच ने कहा कि सेबी को इस प्रकार की सूचना के कुछ हिस्सों को भी उजागर करने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। बैंच ने कहा कि कानून ऐसे चयनित बिन्दुओं के प्रकटीकरण का कभी भी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि ये साफ तौर पर "चैरी पिंकिंग" के बराबर हैं। बैंच ने सेबी को निर्देश दिये कि आर.आई.एल. को न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की पहली तथा दूसरी राय के साथ ही, चार्टर्ड अकाउन्टेंट वाई. एच. मालेगाम, जो सेवानिवृत जज के आदेश से नियुक्त किये गये थे, की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराये।

पूर्व मु.मंत्री पलानीस्वामी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निकालने के लिए पलानिस्वामी ने जिस चाल का इस्तेमाल किया वह यह कि दो नेताओं द्वारा पार्टी का संचालन करने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति रहती है और पार्टी के उद्देश्य और कार्यवाही में एकजुटता की कमी रहती है। पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी में चल रहे इस गुटीय संघर्ष के दो मतलब निकलते हैं- पहला तो इसने डी.एम.के. को अपना शासन अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित किया है और दूसरा, इससे विपक्ष की जगह भी खाली हो गई और भाजपा को इसे भरने का मौका मिल गया।

और तमिलनाडू में ऐसा ही कुछ धीमे-धीमे किन्तु सुनिश्चित रूप से हो रहा है। यानी भाजपा ने विपक्ष के इस रिक्त स्थान को भरना शुरू कर दिया है। उसने भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक कैडर के एक पूर्व अधिकारी के. अन्नामलाई को तमिलनाडू में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो कि बहुत सजग और आक्रामक हैं। अन्नामलाई राज्य के एक मात्र ऐसे विपक्षी नेता हैं जो आम जनता के मुद्दे उठाकर सरकार की कलई खोलते हैं। सरकार और शासन पर उनके निरन्तर फोकस ने स्टालिन सरकार को एक तरह से बैकफुट पर ला दिया है।

केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी की स्थानीय ईकाई का प्रमुख होना, उन्हें स्थानीय राजनीति में कुछ हद तक संबल व तवज्जो प्रदान करता है, खासतौर पर जब बात छोटी पार्टियों से सौदेबाजी की हो। चूंकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के साउथ प्लान में तमिलनाडू को महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए पार्टी को देखना है कि इस राज्य में राजनीति कैसे होती है, बावजूद इसके कि भाजपा यह जानती है कि उसने तो एक ऐसे राज्य में शुरूआत भर की है जहां उसे बाहरी माना जाता है और यहां उसे एक लम्बा रास्ता तय करना है।

एक बाहरी पार्टी की धारणा को समाप्त करना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में डी.एम.के. का मुकाबला करने के लिए डी.एम.डी.के., पी.एम.के. व अन्य छोटी पार्टियों के साथ एक सशक्त गठबंधन बनाने की कार्ययोजना तैयार करनी है। पिछले आम चुनावों में डी.एम.के. राज्य की कुल 39 लोकसभा सीटों में से 38 पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई थी।

पानी निकासी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया है, ताकि नए सिरे से पाईप लाईन डालने का काम जल्द से जल्द करवाया जा सके। आयुक्त ने बताया कि गेनाणी के पास से गुजरने वाली हाईवे की सड़क के नीचे लीकेज हो गया, जिसको ठीक करने के लिए सड़क तोड़कर लीकेज निकालने का काम नगरपरिषद की टीमों द्वारा किया गया। आयुक्त ने बताया कि नया बास में ऐसे अनेक घर हैं, जिनके नीचे से पाईप लाईन गुजरती है। दरअसल 45 साल पहले जब ये पाईप लाईन गेनाणी से पानी निकासी के लिए डाली गई थी, तब इस क्षेत्र में कोई भी मकान नहीं थे। धीरे-धीरे लोग पाईप लाईन को भूल गए और बस्ती में अनेक मकान पाईप लाईन के ऊपर बन गए। नया बास स्थित घनश्याम स्वामी के घर में नींव से पानी की धार निकलने लगी और जब इस बात की शिकायत नगरपरिषद को की गई, तो पता चला कि मकान के नीचे गेनाणी से निकलने वाली पाईप लाईन है। सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद ईदरीश गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया ने बताया कि घरों के नीचे से पाईप लाईन के लीकेज निकालना संभव नहीं है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908